भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1593

जिसका उत्तर सोमवार, 9 फरवरी, 2026/20 माघ, 1947 (शक) को दिया गया

डिजिटल भुगतान तंत्र

1593. श्री ई. टी. मोहम्मद बशीर:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार समाज के सभी वर्गों में अधिक वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल भुगतान तंत्र को किस प्रकार बढ़ा रही है;

(ख) देश के ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में डिजिटल भुगतान अवसंरचना का विस्तार करने और नागरिकों के लिए आसान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए हाल ही में कौन-कौन सी पहल शुरु की गई हैं; और

(ग) नीति निर्माता और विनियामक निकाय किस प्रकार यह सुनिश्चित करते हैं कि डिजिटल लेन-देन का तीव्र विकास देश में दीर्घकालिक वित्तीय सशक्तिकरण और समावेशी आथक विकास में योगदान दे?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) और (ख): सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) और भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों सहित देश में डिजिटल भुगतान इकोसिस्टम को सुदृढ़ करने के लिए विभिन्न पहल कर रहे हैं। इनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, रुपे डेबिट कार्ड को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन योजना और बैंक/फिनटेक को प्रोत्साहित करने के लिए कम मूल्य वाले भीम-यूपीआई लेनदेन (पी2एम) और III से VI स्तरीय केंद्रों में डिजिटल भुगतान बुनियादी ढांचे (जैसे क्यूआर कोड और पीओएस टर्मिनल) के अभिनियोजन की सुविधा के लिए भुगतान अवसंरचना विकास कोष (पीआईडीएफ) शामिल हैं।

पिछले चार वर्ष अर्थात वित्तीय वर्ष 2021-22 से वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, सरकार ने बैंकों और फिनटेक को लगभग 8730 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन सहायता प्रदान की है। इसके अलावा, 31 दिसंबर, 2025 तक निर्बाध डिजिटल भुगतान लेनदेन सुनिश्चित करने के लिए पीआईडीएफ के माध्यम से देशभर में लगभग 5.80 करोड़ डिजिटल टच प्वाइंट्स अभिनियोजित किए गए हैं।

(ग): डिजिटल भुगतान के बढ़ते प्रचलन ने विशेष रूप से वंचित और पिछड़े समुदायों के लिए वित्तीय सेवाओं तक पहुंच में क्रांतिकारी बदलाव ला दिया है ।यूपीआई जैसे प्लेटफॉर्म के माध्यम से निर्बाध, पता लगाने योग्य लेनदेन को सक्षम करके, डिजिटल भुगतान ने व्यक्तियों और व्यवसायों के लिए एक सुदृढ़ वित्तीय पदचिह्न का निर्माण किया है। ये पदचिह्न वित्तीय संस्थानों के लिए वैकल्पिक डेटा बिंदु के रूप में कार्य करते हैं, जिससे ऋण पात्रता का आकलन कर सकते हैं। परिणामस्वरुप, अधिक लोग औपचारिक ऋण माध्यमों तक पहुंच बनाने में सक्षम होते हैं, जो न केवल आर्थिक सहभागिता को सशक्त बनाता है अपितु औपचारिक वित्तीय इकोसिस्टम में अधिक संस्थाओं को भी लाता है। यूपीआई जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म ने छोटे विक्रेताओं और ग्रामीण उपयोगकर्ताओं सहित नागरिकों को डिजिटल भुगतान स्वीकार करने, नकदी की निर्भरता को कम करने तथा औपचारिक आर्थिक भागीदारी बढ़ाने में सक्षम बनाया है।

*****